RNI No.: DEL/BIL/2004/14598

# Youngster

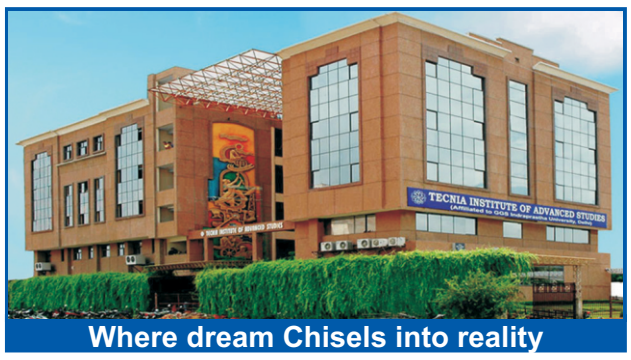

Where dream Chisels into reality

YOUNGSTER · ESTABLISHED 2004 · NEW DELHI · AUGUST 2021 · PAGES 4 · PRICE 1/- · MONTHLY BILINGUAL (HIN./ENG.)

## Webinar organized on Fundamentals of Networks & Embedded Systems, IOT in Tecnia

Tecnia Institute of Advanced Studies organized a seminar on 6th August ,2021. Students of BCA 2nd semester& BCA 4th semester have taken participation in this Seminar. The Seminar was divided into module and sub modules are Introduction to Data & Networking, Fundamentals & Components of IPV4 and IPV6, Tools & Technologies for Subnetting, MAC and IP address implementation, IOT Devices (Resbperry PI, Arduino, Node MCU), Home Automation, Cisco Packet Tracer

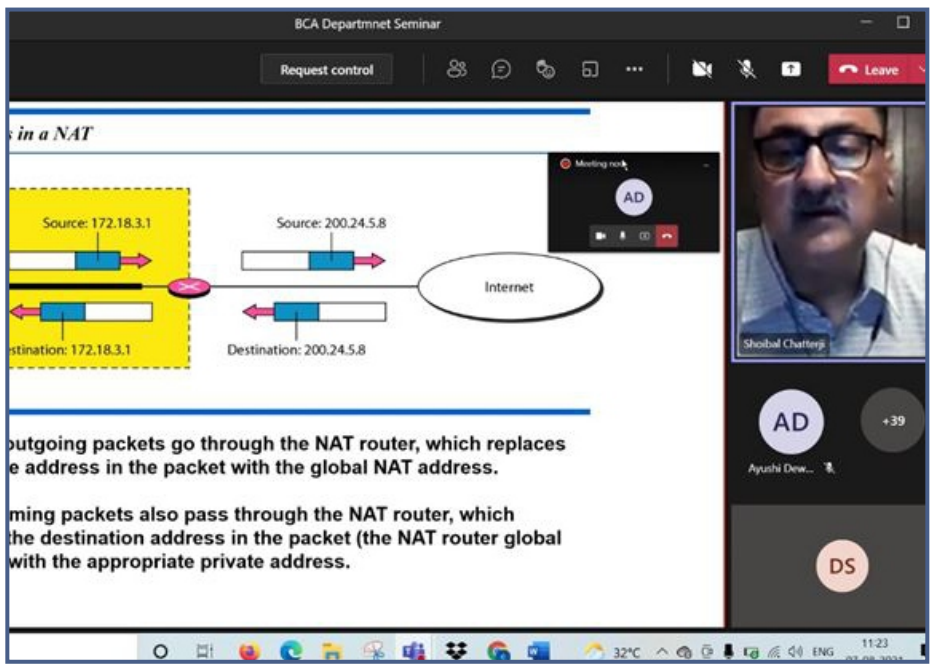


The Seminar started with a welcome speech by Dr. Deepak Sonker, H.O.D of BCA department. In his welcome speech, he asked students to remain focused on Seminar and to put their constant efforts to achieve excellence, learn new innovative things and discussed the significance of Advanced Networks. The Seminar was followed by the introduction speech by Mr. Shoibal Chaterjee and describe in brief about the importance of networking these days. He further continued by explaining the benefits of Network adaptations in future. The Seminar was then carried forward by Mr. Naveen Kumar, Founder and CEO of EMTECH FOUNDATIONS and in the last by Mr Siddharth Tiwari , Presently working with Networking Lions.

Mr. Shoibal explained in detailed about the real world examples also explained the use and importance of unicast, multicast and broadcast networks. In the end of the Seminar, there was a question-answer round, where the students clarified their doubts regarding Networking certifications.

-Dhriti Khanna, BAJMC 3rd Year

## ECO CLUB Organised Webinar on International Mangrove day

Eco Club of Tecnia Institute of Advanced Studies organized one day webinar on International Mangrove Day on 28th August 2021 to celebrate Azadi ka Amurat Mahostav.

The event started with the address of Dr.Ajay Kumar , Director Tias to the special guest. He mentioned that it was a great initiative taken by the Eco club of Tecnia Institute of Advanced Studies to make the students aware about such important days and enhance sensitivity among students with respect to issues related with mangrove. T & P head Dr. Nivedita Mishra has given presentation with significance of Mangrove trees. She told the uses and importance of Mangrove for human survival. She mentioned issues happening with the Mangrove trees in India.

She mentioned the following importance of Mangrove trees. The chief guest Dr Kundan Kumar in his address enlightened the gathering about the significance of man group stay and mangroves tree in India and around the world. He mentioned some unknown facts and figures about mangroves and the ways it is being used and humiliated. Some of the major points covered during the session were Sundarbans in the Gangetic delta with an area of 2.12 lakh hectares (ha) supports 26 plant species of mangrove with a maximum height of more than 10 metres.

**- Vinayak Godra , BAJMC 3rd Year**

## इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में कराने का क्रांतिकारी कदम मोदी जैसे साहसी नेता ही उठा सकते हैं।

यह खुश खबर है कि देश के आठ राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कालेजों में अब पढ़ाई का माध्यम उनकी अपनी भाषाएँ होंगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर इस क्रांतिकारी कदम का कौन स्वागत नहीं करेगा? अब बी. टेक की परीक्षाओं में छात्रगण हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बांग्ला, असमिया, पंजाबी और उड़िया माध्यम से इंजीनियरी की शिक्षा ले सकेंगे। मातृभाषा के माध्यम का यह शुभ–कार्य यदि 1947 में ही शुरू हो जाता और इसे कानून, गणित, विज्ञान, चिकित्सा आदि सभी पाठ्यक्रमों पर लागू कर दिया जाता तो इन सात दशकों में भारत विश्व की महाशक्ति बन जाता और उसकी संपन्नता यूरोप के बराबर हो जाती।दुनिया का कोई भी शक्तिशाली और संपन्न देश ऐसा नहीं है, जहाँ विदेशी भाषा के माध्यम से पढ़ाई होती हो। हिरन पर घास लादने की मूर्खता सिर्फ भारत–जैसे पूर्व गुलाम देशों में ही होती है। इसके विरुद्ध डॉ. लोहिया ने जो स्वभाषा आंदोलन चलाया था, उसका मूर्त रूप अब देखने में आ रहा है। जब 1965–66 में मैंने इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में अपना पीएच.डी. का शोध ग्रंथ हिंदी में लिखने की मांग की थी तो मुझे निकाल बाहर किया गया था। संसद ठप्प हो गई थी लेकिन उसके 50–55 साल बाद अब क्रांतिकारी कदम उठाने का साहस भाजपा सरकार कर रही है। सरकार में दम और दृष्टि हो तो शिक्षा में से अंग्रेजी की अनिवार्य पढ़ाई पर कल से ही प्रतिबंध लगाए और देश के हर बच्चे की पढ़ाई उसकी मातृभाषा में ही हो।

अंग्रेजी समेत कई अन्य विदेशी भाषाएं स्वेच्छया पढ़ने–पढ़ाने की सुविधाएँ विश्वविद्यालय स्तर पर जरूर हों लेकिन यदि शेष सारी पढ़ाई स्वभाषा के माध्यम से होगी तो यह निश्चित जानिए कि नौकरियों में आरक्षण अपने आप अनावश्यक हो जाएगा। गरीबों, ग्रामीणों और पिछड़ों के बच्चे बेहतर सिद्ध होंगे। परीक्षाओं में फेल होने वालों की संख्या घट जाएगी। कम समय में ज्यादा पढ़ाई होगी। पढ़ाई से मुख मोड़ने वाले छात्रों की संख्या घटेगी। छात्रों की मौलिकता बढ़ेगी। वे नए–नए अनुसंधान जल्दी–जल्दी करेंगे। लेकिन भारत की शिक्षा का स्वभाषाकरण करने के लिए सरकार में अदम्य इच्छा–शक्ति की जरूरत है। रातों–रात दर्जनों पाठ्य–पुस्तकें, संदर्भ–ग्रंथ, शब्द–कोश, प्रशिक्षण शालाएँ आदि तैयार करवाने का जिम्मा शिक्षा मंत्रालय को लेना होगा। स्वभाषा में शिक्षण का यह क्रांतिकारी कार्यक्रम तभी अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा, जब सरकारी नौकरियों से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त

होगी। क्या किसी नेता या सरकार में दम है, यह कदम उठाने का? यदि आपने संसद में, अदालतों में, सरकारी काम–काज में और नौकरियों में अंग्रेजी को महारानी बनाए रखा तो मातृभाषाओं की हालत नौकरानियों–जैसी ही बनी रहेगी। मातृभाषाओं को आप पढ़ाई का माध्यम जरूर बना देंगे लेकिन उस माध्यम को कौन अपनाना चाहेगा?

**तेजस्विता उपाध्याय, बीएजेएमसी तृतीय वर्ष**

संपादक की कलम से

# मुस्लिम यदि अपना अतीत खोजेंगे तो उन्हें मोहन भागवत के बयान में सत्यता ही दिखेगी

भारत में प्रामाणिक बयानों का अपने हिसाब से अर्थ निकालना एक परिपाटी–सी बन गई है। विसंगति यह है कि जो प्रचार किया जाता है, उसका मूल बयान से कोई सरोकार ही नहीं होता। एक नई बात गढ़ दी जाती है। इसी को भ्रम फैलाने वाली राजनीति कहा जाता है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि भारत के हिन्दू और मुसलमानों का डीएनए एक है। यह प्रामाणिक रूप से धरातलीय सच है। भारत के मुसलमान अगर अपने परिवार का अतीत खोजेंगे तो उन्हें भागवत जी के बयान में सत्यता दिखाई देगी। मीडिया तंत्र इस बात पर मंथन करे कि जब भारत में मुगलों का आक्रमण नहीं हुआ था, उस समय भारत में कोई मुसलमान था ही नहीं। अतरू यह स्वाभाविक है कि आज हमारे देश में जो मुसलमान हैं, उनके पूर्वज हिन्दू ही थे। फारुक अब्दुल्ला कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के वंशज हैं। इसी प्रकार अन्य मुसलमानों की विरासत हिन्दू अवधारणा वाली ही है। जहां तक हिन्दू अवधारणा का सवाल है तो यही कहना समुचित होगा कि हिन्दू दर्शन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। इसी कारण कई मुसलमान घर वापसी कर रहे हैं।यह बात सही है कि वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से पहचाने वाला देश पूर्व में भारत का ही हिस्सा रहा था। इसलिए उसका इतिहास भारत के बिना अधूरा है और इसी कारण भारत के मुसलमानों का इतिहास हिन्दू समाज या भारतीय समाज से अलग हो ही नहीं सकता। सच्चाई को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान का कई बुद्धिजीवी मुसलमानों ने समर्थन भी किया है, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति के चलते मुसलमान मुख्य धारा से कट रहा है। उसे हिन्दू के नाम से डराया जा रहा है। जबकि वास्तविकता यही है कि मुसलमानों के त्यौहारों में हिन्दू समाज भी सहयोग करता रहा है। इसके विपरीत तुष्टिकरण की राजनीति के बहकावे में आकर मुसलमान भारत के मूल त्यौहारों से अलग होता जा रहा है। सवाल यह है कि इस प्रकार की राजनीति देश की एकता के लिए बड़ा खतरा है। मंथन इस बात का भी करना होगा कि दुनियाभर में जितने भी मुसलमान निवास करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत में ही हैं। आज कुछ मुसलमान संदेह की दृष्टि से देखे जा रहे हैं, उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण स्वयं मुसलमान ही हैं, जो मुख्य धारा में आना भी चाहते हैं, लेकिन राजनीति ऐसा नहीं करने दे रही। उन्हें अपने वोटों की चिंता है।

भारत को स्वतंत्रता मिलने से पूर्व भारतीय समाज को तोड़ने का जो कुचक्र अंग्रेजों ने रचा था, भारत के राजनेताओं ने उसी नीति को आत्मसात करते हुए ऐसी राजनीति की कि आज समाज छिन्न–भिन्न हो गया। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस छिन्न–भिन्न समाज को एक करने का प्रयास कर रहा है तो इन राजनेताओं के पेट में दर्द उठना स्वाभाविक है। जहां तक वर्तमान केन्द्र सरकार की बात है तो उसने मुस्लिम समाज की महिलाओं के दर्द को कम करने का साहस दिखाया है। तीन तलाक का डर दिखाकर मुस्लिम महिलाओं के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती रही थी, अब उससे मुक्ति मिल गई है। यह कदम वास्तव में मुस्लिम समाज को आगे लाना वाला ही है। लेकिन कई लोगों को इस कदम में भी मुस्लिम विरोध दिखाई दिया, जो पूरी तरह से गलत है। यह देश का दुर्भाग्य है कि इने–गिने लोग ऐसे हैं, जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की एकता–अखंडता को क्षति पहुँचाने में लगे रहते हैं।

यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि विदेशी मुस्लिम बादशाहों ने भारत पर कभी लूटपाट के लिए और कभी अपनी सत्ता स्थापित कर इस्लामी झंडा फहराते हुए भारत की धर्म, संस्कृति, परम्परा को क्रूरता से कुचलने की लगातार कोशिश की। चाहे बाबर, तैमूर, गौरी हो या औरंगजेब हो, सभी की बर्बरता की कहानी इतिहास चीख–चीखकर कह रहा है। इतिहास को कुरेदकर यह समीक्षा करने की प्रासंगिकता नहीं है कि ये क्रूर हमलावर क्यों सफल हुए, भारत की राजशक्ति इस क्रूरता का प्रतिकार क्यों नहीं कर सकी। इस सबकी तह में जाने से यह पता चलता है कि कहीं न कहीं भारतीय समाज में अपने देश के प्रति निष्ठा कमजोर थी, लेकिन आज एक बात दिखाई देने लगी है कि भारतीय युवा अपने धर्म के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन कर रहा है और ऐसा करने में उसे गौरव का अहसास भी होता है। हम देखते हैं कि देश के विरोध में उठने वाली हर आवाज का हर स्तर पर सटीक जवाब दिया जाने लगा है। हम यह भी जानते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो गलत काम करते हैं, वे लोग अच्छे कामों की बुराई ही करेंगे।

वर्तमान में भारत की करीब बीस प्रतिशत आबादी मुस्लिमों की है। इनके पूर्वज हमलावरों की क्रूरता के शिकार हुए और अपने परिवार की जीवन रक्षा के लिए इन्होंने मजबूरी में इस्लाम कबूल किया। इसलिए इस सच्चाई को कैसे नकारा जा सकता कि इनके पूर्वज हिन्दू थे। इस प्रकार के सम्प्रदाय और उपासना पद्धति का विकास देश की माटी से होता है, इसलिए भारत का इस्लाम, सऊदी अरब का इस्लाम नहीं हो सकता। भारत की सर्वव्यापी संस्कृति के विचार प्रवाह के साथ ही भारत के मुस्लिमों को चलना होगा, क्योंकि उनका जिन्स और हिन्दुओं का जिन्स समान है, जो इस खून के रिश्ते को तोड़कर भारत के मुस्लिमों को देश की माटी से अलग करना चाहते हैं, वे छद्म देशद्रोही हैं, उनकी कोशिशों को असफल करना, हर देशभक्त का दायित्व है।

हालांकि सऊदी अरब और पाकिस्तान की साजिश में शामिल होने से अब भारतीय मुसलमान भी किनारा करने लगे हैं। देश का मुसलमान अब पूरी तरह से विकास की धारा के साथ आना चाहता है, लेकिन हर बार की तरह वह राजनीति का शिकार हो जाता है। मुसलमान को जितना सम्मान भारत में दिया जाता है, उतना किसी भी गैर इस्लामिक देश में नहीं मिल सकता और न ही मिलने की उम्मीद है। यह सही है कि राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को केवल भय दिखाकर वोट के रूप में प्रयोग किया। वर्तमान में देश का मुसलमान इस सत्य को समझ चुका है और वह भी सबका साथ सबका विकास के भाव को अंगीकार करके अपना विकास चाहता है।

# मोदी मंत्रिमंडल आजाद भारत के इतिहास में सबसे युवा और पढ़े लिखे नेताओं की टीम है

मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का ताजा विस्तार जहां कई उम्मीदों को जगाता–सा दिखता है वहीं वो अपनी कई नाकामियों पर पर्दा डालता भी नजर आता है। क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा के कई दिग्गजों से इस्तीफा लेकर नए चेहरों को सरकार में जगह दी गई है उससे इसे मंत्रिमंडल विस्तार न कहकर मंत्रिमंडल सुधार कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। इतना ही नहीं मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेन्स के मंत्र पर चलने वाले प्रधानमंत्री मोदी के इस मंत्रिमंडल विस्तार में 43 मंत्रियों ने शपथ ली है और इसी के साथ मोदी सरकार में मंत्रियों की संख्या 78 तक पहुंच गई है। इस मंत्रिमंडल विस्तार ने कई प्रश्न उत्पन्न किए हैं तो कई संदेश भी दिए हैं।

दअरसल कोरोना काल की शुरुआत में या फिर कोरोना की पहली लहर के दौरान जब कोरोना के कारण पूरे विश्व में तबाही मची हुई थी तब ऐसा लग रहा था कि भारत ने कोरोना को काबू में कर लिया है। अपने सीमित संसाधनों और विशाल जनसंख्या के बावजूद भारत खुद को कोरोना की तबाही से बचाने में कामयाबी हासिल करके सम्पूर्ण विश्व को चौंका चुका था। मोदी सरकार मोदी ब्रांड बन चुकी थी लेकिन कोरोना की दूसरी लहर समुद्र में उठी सुनामी की वो लहर साबित हुई जिसने वर्तमान सरकार की कार्यक्षमता और उसकी प्रशासनिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उस ब्रांड पर ही पानी फेर दिया।

जिस प्रकार से देश में साधारण एंटीबायोटिक से लेकर जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी हुई या फिर ऑक्सिजन की कमी से हजारों जानें गईं और अस्पतालों में बिलों के द्वारा लूट का उपक्रम शुरू हुआ, आम आदमी के मन में प्रश्न उठने लगा था कि इस देश में प्रशासन नाम की कोई चीज भी है या फिर जंगल राज है।

यह सब विशेष रूप से इसलिए भी निराशाजनक था क्योंकि आम आदमी के साथ यह सब उस सरकार के शासन काल में हो रहा था जिस सरकार को उसने बेहद उत्साह और उम्मीदों के साथ दूसरी बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ मौका दिया था। शायद आम जनमानस के हृदय में उपजी यही निराशा इस मंत्रिमंडल विस्तार के अनेक कारणों में से एक कारण रहा हो। क्योंकि मोदी जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ यह अच्छी तरह जानता है कि नोटबन्दी या जीएसटी या फिर पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों जैसे विषयों में भले ही लोग अपने नेता की नीयत देखते हों लेकिन जब बात आम आदमी के जीवन, उसके स्वास्थ्य, उसके अस्तित्व पर ही आ जाती है तो वो ही जनमानस नीयत नहीं नतीजे देखता है।

और कोरोना काल के निराशाजनक नतीजे किसी से छिपे नहीं हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार में स्वास्थ्य मंत्री को बदल कर सरकार भले ही यह संदेश देने का प्रयास करे कि जो मंत्री नतीजे नहीं देगा वो हटा दिया जाएगा लेकिन यह संदेश आम आदमी के दिल तक कितना पहुंचता है यह तो समय ही बताएगा।

यही कारण है कि पांच राज्यों में आगामी चुनावों को देखते हुए तमाम राजनैतिक समीकरणों को साधने का लक्ष्य भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में छुपा है। इसी को देखते हुए देश के इन प्रदेशों के प्रतिनिधियों को शामिल करने से लेकर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को इस मंत्रिमंडल में विशेष रूप से शामिल किया गया। इसके अलावा एनडीए के घटक दलों जैसे जनता दल युनाइटेड, लोकजनशक्ति पार्टी और अपना दल को भी इस कैबिनेट विस्तार में शामिल करके भाजपा ने एनडीए को भी मजबूती प्रदान की है।

लेकिन राजनीति से इतर अगर इस मंत्रिमंडल विस्तार के सकारात्मक पक्ष की बात की जाए तो यह मंत्रिमंडल शायद आजाद भारत के इतिहास में अब तक का सबसे युवा और पढ़े लिखे नेताओं का मंत्रिमंडल है। योग्यता की बात करें तो इसमें सात पीएचडी, तीन एमबीए, तेरह वकील, छह डॉक्टर, पांच इंजीनियर और सात सिविल सेवक मंत्री हैं।

भारत जैसे देश की राजनीति में निश्चित ही यह एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक स्वागतयोग्य बदलाव है। क्योंकि इस देश ने राजनीति में योग्यता के अभाव के बावजूद परिवारवाद अथवा भाई भतीजावाद या फिर वोटबैंक के दम पर अंगूठाछाप से लेकर ऐसे नेताओं को देश के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे देखा है जिन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। देश की राजनीति में ऐसे माहौल से जनता त्रस्त थी और राजनेताओं से उनका मोहभंग होने लगा था।

लेकिन इस मंत्रिमंडल में शिक्षित और युवा नेताओं को सरकार में शामिल किया जाना जहां एक ओर आम लोगों के मन में उम्मीद जगाता है तो दूसरी ओर नेताओं को कड़े संदेश भी देता है। इस प्रकार के कदम निश्चित ही देश की राजनीति में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश इस कैबिनेट विस्तार के द्वारा प्रधानमंत्री ने दिया है वो यह कि वो महिला सशक्तिकरण की केवल बात ही नहीं करते बल्कि उस दिशा में ठोस कदम भी उठाते हैं।

वित्त, विदेश और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय महिलाओं के हाथ में देकर वो पहले भी महिलाओं में अपना विश्वास व्यक्त कर चुके थे। इस बार उन्होंने सात मंत्रालय महिलाओं के हाथों में सौंपे हैं और अब कुल 11 महिलाएं वर्तमान सरकार में मंत्री हैं जो महिलाओं के प्रति बदलते दृष्टिकोण का प्रतीक है। तो कहा जा सकता है कि कैबिनेट का यह विस्तार भले ही राजनैतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखकर या छवि बदलने की कोशिश में किया गया हो लेकिन इसमें राजनैतिक शुचिता और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलने जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी विषयों पर जोर देकर वर्तमान राजनीति की दिशा बदलने का एक गंभीर प्रयास भी किया गया है जिसके लिए प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। राजनैतिक हितों को साधते हुए इससे बेहतर मंत्रिमंडल विस्तार शायद नहीं हो सकता था।

**चंदन कुमार, बीएजेएमसी तृतीय वर्ष**

## THIS MONTH

**August 15, 1969** - Woodstock began in a field near Yasgur's Farm at Bethel, New York. The three-day concert featured 24 rock bands and drew a crowd of more than 300,000 young people. The event came to symbolize the counter-culture movement of the 1960's.

*****

**August 12, 1676** - King Philip's War ended with the assassination of Metacom, leader of the Pokanokets, a tribe within the Wampanoag Indian Federation. Nicknamed 'King Philip' by colonists, he led a Native American uprising against white settlers which resulted in a war that raged for nearly two years, now known as King Philip's War.

*****

**August 16, 1777** - During the American Revolutionary War, the Battle of Bennington, Vermont, occurred as militiamen from Vermont, aided by Massachusetts troops, wiped out a detachment of 800 German-Hessians sent by British General Burgoyne to seize horses.

*****

**August 16, 1780** - The Battle of Camden in South Carolina occurred during the American Revolutionary War. The battle was a big defeat for the Americans as forces under General Gates were defeated by troops of British General Charles Cornwallis, resulting in 900 Americans killed and 1,000 captured.

**Compilation:**
Ishita

## BASICS OF MEDIA

**Camcorder:** A portable camera with the videotape recorder or some other recording device attached or built into it to form a single unit.

*****

**Control Room:** A room adjacent to the studio in which the director, the technical director, the audio engineer, and sometimes the lighting director perform their various production functions.

*****

**Expanded System:** A television system consisting of equipment and procedures that allows for selection, control, recording, playback, and transmission of television pictures and sound.

*****

**Feed:** Signal transmission from one program source to another, such as a network feed or a remote feed.

*****

**Line Monitor:** The monitor that shows only the line-out pictures that go on the air or on videotape. Also called master monitor or program monitor.

*****

**Line-out:** The line that carries the final video or audio output for broadcast.

*****

*To Be Continued In Next Issue-*

**Compilation:**
Anmol

# महंगाई की मार से बेहाल हैं लोग, मोदी सरकार को जल्द ही कुछ करना चाहिए

केंद्र सरकार ने हाल ही में घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी करके महंगाई से बेहाल देश की जनता को एक और झटका दिया है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से देश का आम जन पहले से ही पूरी तरह पिसा हुआ है। ऊपर से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी करना आम आदमी के लिए बहुत ही दुखदाई है। देश में आज पेट्रोल और डीजल एक सौ रुपए से अधिक प्रति लीटर की दर पर बिक रहे हैं। ऐसे में रसोई गैस की कीमत बढ़ाना बहुत बरा फैसला है। पिछले चौदह महीनों से लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिलना भी बंद है।

पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी के बाबत पिछले दिनों पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बयान भी दिया था कि कोरोना संकट के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को कम करना मुनासिब नहीं है। प्रधान का यह बयान उन मतदाताओं के साथ सरासर अन्याय है। जिन्होंने भाजपा को गरीबों की हितैषी पार्टी मानकर लगातार दो बार भारी बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था।

देश की जनता पिछले सवा साल से लगातार कोरोना संक्रमण को झेल रही है। इस दौरान अधिकांश समय देश में लॉकडाउन लगने से लोगों को घरों में ही रहना पड़ा है। ऐसे में काम धंधे बंद होने से आम आदमी के रोजगार के अवसर समाप्त होने से उनके आय के स्त्रोत बंद हो गये। जिससे आम आदमी की कमर टूट चुकी है। दिनों दिन बढ़ती महंगाई और लगातार कम होते काम के अवसर ने देश की जनता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। खाने का तेल दुगुनी दर पर बिक रहा है।

कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों पर कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी से खूब कमाई हुई है। सरकार को अप्रत्यक्ष कर से आने वाला राजस्व बढ़कर 4.51 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वित्तीय वर्ष 20–21 में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर 37 हजार 806. 96 करोड़ रुपए कस्टम ड्यूटी वसूली गई। वहीं देश में इनके उत्पाद पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 4.13 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। 2019–20 में पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर सरकार को कस्टम ड्यूटी के रूप में 46 हजार करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। वहीं देश में इनके उत्पाद पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 2.42 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई। अब अगर दोनों तरह की टैक्स वसूली को देखें तो सरकारी खजाने में 2019–20 में कुल 2.88 लाख करोड़ रुपए जमा हुए। महंगे पेट्रोल–डीजल से केवल आम आदमी ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ गई है। जो पहले से ही कोरोना महामारी की मार झेल रही है। केन्द्र सरकार को तत्काल पेट्रोल–डीजल पर टैक्स घटाकर लोगों को महंगाई से राहत देनी चाहिये।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के बावजूद भी सरकार का कर संग्रहण लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि देश की जनता को कोरोना वैक्सीन के टीके मुफ्त में लगाए जा रहे हैं। जिन पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए सरकार को टैक्स में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। मगर सरकारी सूत्रों के अनुसार ही देश के लोगों के टीकाकरण पर अधिकतम 40 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। जबकि सरकार ने कोरोना संक्रमण के बाद बढ़ाए गए टैक्स से कई लाख करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण किया है।

केन्द्र सरकार ने पहले 20 लाख करोड़ का तथा गत दिनों सात लाख करोड़ रुपयों के राहत पैकेज की घोषणा की थी। मगर सरकार की इन घोषणाओं का भी आम आदमी को विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है। पैसों के अभाव में लोगों से बिजली के बिल जमा नहीं हो पा रहे हैं। जिन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है उनकी किस्तों की भरपाई नहीं हो पा रही है। ऊपर से निजी स्कूल वाले भी बिना पढ़ाई बच्चों से जबरन फीस वसूल रहे हैं। जो गरीबों पर सीधा कुठाराघात है।

कोरोना संक्रमण के दौरान बीमार हुए लोगों को उपचार पर बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ा है। जिसकी भरपाई का लोगों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कोरोना से मरने वाले लोगों को सरकारी स्तर पर कुछ मुआवजा मिलने की संभावनाएं बनी हैं। मगर अधिकांश लोगों की मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना से मौत होना दर्ज ही नहीं किया गया है। ऐसे में उन लोगों को मुआवजा मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। यदि केन्द्र सरकार चाहे तो अस्पतालों को निर्देशित कर सकती है कि कोरोना संक्रमण के दौरान जिनकी वास्तव में कोरोना से मौत हुई है। उनको कोरोना से मौत का प्रमाण मृत्यु पत्र दिया जाये ताकि उनको भी मुआवजा मिल सके।

देश में कोरोना की प्रथम लहर के दौरान ही सरकार ने रेल सेवा पूरी तरह से बंद कर दी थी। कई महीनों के बाद सरकार ने कुछ रेलगाड़िया प्रारंभ की हैं। जिनमें सफर करने के लिए लोगों को पहले से अधिक किराया चुकाना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार वर्तमान में संचालित सभी रेलगाड़ियों को स्पेशल ट्रेन के रूप में चला रही है। जिसका किराया सामान्य से काफी अधिक होता है। चूंकि रेलगाड़ियों में अमूमन आम आदमी यात्रा करता है जो पहले ही कोरोना के कारण आर्थिक मार से परेशान है। ऐसी स्थिति में उससे रेल भाड़े के रूप में भी अधिक राशि वसूल करना केन्द्र सरकार का न्याय संगत फैसला नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि मैं दिन–रात देश की जनता की उन्नति की बातें सोचता हूं व करने का प्रयास करता हूं। मगर ना जाने वह मौजूदा स्थिति से क्यों अनजान बने हुए हैं। देश का आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान वर्ग को ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है जिससे आगे चलकर वह अपनी कोरोना आने से पहले की जिंदगी बसर कर सके। गांव में तो स्थिति और भी खराब हो रही है। कोरोना के कारण शहरों से पलायन कर अपने गांव आए हुए लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है।

हालांकि केंद्र सरकार ने प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं प्रतिमाह मुफ्त में देने की घोषणा की है। मगर व्यक्ति को जिंदगी जीने के लिए गेहूं के साथ अन्य बहुत–सी चीजों की जरूरत होती है। जिनको खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। केन्द्र सरकार को शीघ्र अति शीघ्र महंगाई को काबू में करने के उपाय करने चाहिए। सिर्फ कागजी घोषणाओं से ही लोगों का भला नहीं होने वाला है।

केन्द्र को आम लोगों के हित की योजनाओं को धरातल पर उतारना होगा। अन्यथा बेरोजगारी के साथ महंगाई से त्रस्त देश की जनता लंबे समय तक चुप बैठने वाली नहीं है। देश में बढ़ रही महंगाई का धनवान लोगों पर तो कोई असर नहीं है। मगर आम नागरिकों पर सीधा असर पड़ता है। किसी भी सरकार को बनवाने या हटवाने में आम आदमी की ही सबसे बड़ी भूमिका होती है। अतः समय रहते केंद्र सरकार को महंगाई पर रोक लगाकर आम आदमी की पूरी मदद करनी चाहिए।

**रिषभ अग्रवाल, बीएजेएमसी तृतीय वर्ष**

# उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पूजन में क्यों जुटे हैं राजनीतिक दल ? सत्ता के लिए क्यों जरूरी है ब्राह्मणों का आशीर्वाद

हमारे देश की जाति व्यवस्था में ब्राह्मण को गुरु, पूज्य और यहाँ तक कि तीर्थस्वरूप माना गया है। कोई भी शुभ कार्य करना हो, ब्राह्मण ही उसे संपन्न कराता है। पौराणिक ग्रंथों को देखेंगे तो उल्लेख मिलेगा कि ब्राह्मण को कभी निराश नहीं करना चाहिए और ब्राह्मणों को दिये जाने वाला दान–दक्षिणा जन्म जन्मांतरों तक अक्षय फल प्रदान करता है। लेकिन आज की राजनीति की बात करें तो नेता भले चुनावों में जीत का आशीर्वाद लेने ब्राह्मण के पास आते हों लेकिन सत्ता में भागीदारी के मामले में ब्राह्मणों को उनका असल हक नहीं दिया जाता। लेकिन ब्राह्मणों का इतिहास है कि उन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया ना ही अपने हक के लिए कोई बड़ी लड़ाई लड़ी है। ब्राह्मण का प्रयास रहता है कि समाज में शांति और समृद्धि बनी रही जिससे उसका भी काम चलता रहे। आमतौर पर ब्राह्मण को काम पड़ने पर ही याद किया जाता है और अब चूँकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ गये हैं तो प्रदेश में वोटों के लिहाज से बड़ा महत्व रखने वाले इस समुदाय को लुभाने की कवायद भी तेज हो गयी है।

सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से साल 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी बसपा ने फिर से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने की बात कही है तो भाजपा ब्राह्मण नेताओं को पार्टी में शामिल कराने का अभियान चलाये हुए है और आने वाली गुरु पूर्णिमा पर भाजपा नेता और जनप्रतिनिधि मठों और मंदिरों में दस्तक देने की तैयारी में हैं। यही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी मंत्रिपरिषद का जो विस्तार और फेरबदल किया है उसमें उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरणों को देखते हुए ब्राह्मण नेता को भी जगह दी है। मोदी सरकार में देखें तो कुल मिलाकर 11 ब्राह्मण मंत्री हैं। इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि योगी सरकार के संभावित विस्तार में कांग्रेस से भाजपा में आये ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद को जगह दी जा सकती है। योगी सरकार में इसके अलावा पहले से ब्रजेश पाठक जैसे बड़े ब्राह्मण नेता कैबिनेट मंत्री हैं ही।

उत्तर प्रदेश में आबादी के लिहाज से नजर डालें तो भले ब्राह्मणों की संख्या 13 प्रतिशत के आसपास ही है लेकिन कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। पिछले विधानसभा चुनावों की ही बात करें तो 56 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार विजयी हुए थे। इन 56 में से 44 तो भाजपा के ही विधायक थे। यानि ब्राह्मण मतदाताओं ने भाजपा को दिल खोल कर वोट दिया था। एक और बड़ा आंकड़ा यह है कि पिछले तीन विधानसभा चुनावों में जिसके पास सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक रहे उसी पार्टी की ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। वर्तमान की बात करें तो भाजपा ने भी योगी सरकार बनने पर दिनेश शर्मा के रूप में ब्राह्मण नेता को उपमुख्यमंत्री पद दिया और कुल मिलाकर योगी सरकार में इस वर्ग के 8 विधायकों को मंत्री पद दिये गये। लेकिन यह सभी ब्राह्मण मंत्री अपने समुदाय के बीच योगी सरकार के कामकाज को सही से प्रचारित भी नहीं कर पाये और ना ही अपने समुदाय के बीच यह मंत्री कोई खास पैठ बना पाये। आप आसान से उदाहरण से समझिये। योगी सरकार में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जितनी पिछड़ों के बीच पैठ है क्या उतनी पैठ दिनेश शर्मा की ब्राह्मणों के बीच है? उत्तर होगा नहीं।

**क्या ब्राह्मण योगी सरकार से नाराज हैं?**

देखा जाये तो ब्राह्मणों के बारे में अफवाहें फैलाना भी आसान है क्योंकि वह कभी इसका खंडन करने आगे नहीं आते। जो चल रहा होता है उसे चलने देते हैं, यह सोच कर कि एक दिन प्रभु कृपा से सच सामने आ ही जायेगा। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसके कई और साथी भी मारे गये तो मीडिया के एक वर्ग ने खबरें चला दीं कि ब्राह्मण योगी सरकार से नाराज हो गया है क्योंकि कई ब्राह्मणों का एनकाउंटर करवा दिया गया। इस प्रकार की खबरें इतनी ज्यादा चलीं कि शायद योगी सरकार को भी लगने लगा होगा कि इसी कारण से ब्राह्मण उससे नाराज है। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि पौराणिक ग्रंथों का नित वाचन करने वाले और उसमें उल्लिखित संदेशों से सभी को अवगत कराने वाला ब्राह्मण आदिकाल से ही जागरूक है और जानता है कि अपराधी या आतंकवादी का अपना कोई धर्म या जाति नहीं होती और यदि कोई अपराधी या आतंकवादी है तो उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होनी ही चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। वैसे ब्राह्मण यदि सरकार से नाराज है तो अपने साथ होने वाले भेदभाव से नाराज है, अपने बच्चों के शिक्षा और नौकरियों के खोते अवसरों से नाराज है। भाजपा को पता है कि ब्राह्मण नाराज रहे तो हिंदुत्व कार्ड खेलने में परेशानी होगी इसलिए उन्हें मनाने में जुटी हुई है।

**बहनजी को ब्राह्मण क्यों याद आये ?**

दूसरी ओर मायावती को 14 साल बाद यदि ब्राह्मणों की याद आई है तो यकीनन कुछ तो इस समुदाय की ताकत होगी। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में मायावती 50 से ज्यादा टिकट ब्राह्मणों को दे सकती हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण मतदाता बसपा की ओर फिर झुकेंगे। साल 2009 के लोकसभा चुनावों के बाद से हुए सभी चुनावों के आंकड़े तो यही दर्शाते हैं कि इस वर्ग ने बसपा से लगभग किनारा कर लिया है। मायावती तो यहाँ तक ऐलान कर चुकी हैं कि यदि वह सत्ता में आती हैं तो भगवान परशुराम की सपा से भी ऊँची मूर्तियां लगवाएंगी और भगवान परशुराम के नाम पर पार्कों तथा अस्पतालों के नाम भी रखे जाएंगे। बहरहाल, मायावती ने जिन सतीश चंद्र मिश्र को ब्राह्मण सम्मेलनों के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी है वह आम ब्राह्मणों का तो नहीं लेकिन अपने परिवार के ब्राह्मणों का राजनीतिक भला करने में जरूर कामयाब रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्र भले बसपा के साथ बने रहे लेकिन पार्टी के कई बड़े ब्राह्मण नेता मायावती का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में अयोध्या से शुरू होने वाले बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन कितना प्रभाव डाल पाएंगे यह देखने वाली बात होगी। खासतौर पर ब्राह्मण यह भी देख रहे हैं कि चुनावों से छह महीने पहले ही मायावती ने ब्राह्मणों की सुध ली है।

सपा की क्या योजना है?

ब्राह्मण समुदाय को लुभाने की कोशिश में समाजवादी पार्टी प्रदेश में भगवान परशुराम की मूर्तियाँ लगवाने का ऐलान कर चुकी है। लखनऊ में तो 108 फुट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई भी जा रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के तीन ब्राह्मण नेताओं– अभिषेक मिश्र, माता प्रसाद पांडे और मनोज पांडे को जिम्मेदारी सौंपी है कि ब्राह्मणों को सपा के पक्ष में एकजुट किया जाये। सपा दिवंगत जनेश्वर मिश्र के नाम पर भी ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास करती रहती है।

**क्या कांग्रेस के पास कोई ब्राह्मण नेता बचा है ?**

वहीं जितिन प्रसाद के जाने के बाद कांग्रेस के पास अब प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला और ललितेशपति त्रिपाठी जैसे बड़े ब्राह्मण नेता ही बचे हैं लेकिन इनका कितना बड़ा जनाधार है यह सब जानते हैं। कांग्रेस की योजना गांधी परिवार को ही उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े ब्राह्मण परिवार के रूप में प्रचारित करने की है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि वही एकमात्र पार्टी है जिसने प्रदेश को ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिये। उल्लेखनीय है कि आजादी के बाद से 1989 तक उत्तर प्रदेश में छह बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। प्रदेश के अंतिम ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी थे जिन्होंने तीन बार प्रदेश की कमान सँभाली थी।

बहरहाल, जहाँ तक मायावती का यह कहना है कि वर्तमान शासन में ब्राह्मण समाज बहुत ज्यादा दुखी है और उसे अब भाजपा को तिलांजलि दे देनी चाहिए, इस पर यही कहा जा सकता है कि ब्राह्मण को बरगलाया या खरीदा नहीं जा सकता वह देश और समाज हित में सही निर्णय लेने का शुरू से ही आदी रहा है। ब्राह्मण सभी नेताओं की बात और राजनीतिक दलों के वादे सुनता जरूर है लेकिन करता वही है जो शास्त्र सम्मत होता है।

**हिमांशु कुमार सिंह, बीएजेएमसी तृतीय वर्ष**

# कोरोना अभी गया नहीं है, जिस तरह की लापरवाही हो रही है वह देश को भारी पड़ सकती है

विश्व स्वास्थ्य संगठन व दुनिया के बड़े वैज्ञानिक व चिकित्सा विशेषज्ञ सभी देशों को लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि वह अपने यहां लगाई गई पाबंदियों में ढील ना दें। दुनिया भर में जल्दी ही कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। कई देशों में तो कोरोना की तीसरी लहर प्रारंभ भी हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर में कोरोना का वायरस पहले से ज्यादा प्रभावी होगा, जिसके बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस समेत कई बड़े देशों में कोरोना के बढ़ते आंकड़े भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बावजूद जिस तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार–बार लोगों को चेता रहे हैं कि बेवजह घरों से निकलकर अनावश्यक भीड़भाड़ इक्कठी ना करें।

केरल में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में केरल सरकार की ओर से बकरीद पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई व जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि यह अफसोस की बात है कि राज्य सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई। उन इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति दी जहां कोरोना दर 15 फीसदी से अधिक है और लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है।

कोरोना की दूसरी लहर के बाद किए गए सीरो सर्वे में देश के 68 फीसदी लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें टीका लगाया जा चुका है। इसके बावजूद प्रतिदिन नये कोरोना मरीजों के आंकड़ों का 40 हजार के आसपास रुक जाना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। विशेषज्ञों ने चिंता जताते हुए कहा है कि कोरोना के आंकड़े जिस तरह से स्थिर हो गए हैं। उसे देखने के बाद संभावना है कि आंकड़ों में बहुत जल्दी बढ़ोत्तरी देखने को मिले। देश के 13 राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है। केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के अलावा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं।

देश में अभी प्रतिदिन 40 हजार कोरोना के नए केस मिल रहे हैं। जबकि देश में पहली बार संपूर्ण लॉकडाउन लगा था तब मात्र 85 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे। उससे तुलना करें तो वर्तमान स्थिति बहुत चिंताजनक है। देश में अभी तक तीन करोड़ नौ लाख के करीब कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। जिनमें से तीन करोड़ पांच लाख यानी 99 प्रतिशत कोरोना पॉजिटिव केस रिकवर हो चुके हैं। वही 4 लाख 20 हजार लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है जो एक प्रतिशत है। देश में अभी तक कोरोना के 35 करोड़ नमूने लेकर उनकी जांच की जा चुकी है। वर्तमान में भी प्रतिदिन 17 से 18 लाख कोरोना के नमूनों की देश में जांच की जा रही है।

पूर्वोत्तर के आठ प्रदेशों में कोरोना पॉजिटिव केसों में एकाएक बढ़ोतरी होना बड़ी चिंता का विषय है। कोरोना की पहली लहर में पूर्वोत्तर के आठ प्रदेश कोरोना से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। मगर इस बार वहां कोरोना का काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। अभी देश में कोरोना से प्रतिदिन होने वाली मौत का आंकड़ा 500 से अधिक है।

**ऋतिक जोशी, बीएजेएमसी तृतीय वर्ष**

**Vol.** 14 **No.** 8
**RNI No.:** DEL/BIL/2004/14598
**Publisher:** Ram Kailsah Gupta on behalf of Tecnia Institute of Advanced Studies, 3 PSP, Madhuban Chowk, Rohini, Delhi-85; **Printer:** Ramesh Chander Dogra; **Printed at:** Dogra Printing Press, 17/69, Jhan Singh Nagar, Anand Parbat, New Delhi-5
**Editor:** Bal Krishna Mishra responsible for selection of News under PRB Act.
All rights reserved.

## IMPORTANT QUOTES

"I do not consider it an insult, but rather a compliment to be called an agnostic. I do not pretend to know where many ignorant men are sure -- that is all that agnosticism means."

***- Clarence Darrow***

*****

"Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal."

***- Henry Ford***

*****

"I'll sleep when I'm dead."

***- Warren Zevon***

*****

"There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread."

***- Mahatma Gandhi***

*****

**Compilation:** Anmol

## WINNERS v/s LOOSERS Part-90

Winners
dreams;
losers have schemes.
schemes.

*****

Winners say,
"I must do something";
losers say,
"Something must be done."

*****

Winners are a part of the team;
losers are apart from the team.

*****

Winners
makes commitments;
Losers
makes promises.

*****

Winners
see the gain;
losers
see pain.

*****

*To Be Continued In Next Issue-*

**Compilation:** Dhriti Khanna

All Students and Faculty are welcome to give any Article, Feature & Write-up along with their Views & Feedback at: **youngstertias@gmail.com**